

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती- दो हजार तेइस के अंतर्गत चयनित 912 अभ्यर्थियों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज है। प्रदेश की छवि को बदलने में यूपी पुलिस का सराहनीय योगदान रहा है।

आज यूपी के इस ओवरऑल परसेप्शन में जो बदलाव आया है, इस बदलाव में एक बड़ी भूमिका यूपी पुलिस की है और यूपी पुलिस ने वह करके दिखाया है जो कभी यूपी के अंदर नहीं हुआ था और आज उसी का परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। हमने उपद्रवग्रस्त प्रदेश को उसकी सही पहचान उत्सवपूर्ण प्रदेश के रूप में बदला है। कर्फ्यू मुक्त और माफिया मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की छवि को प्रस्तुत किया है।

इसके बाद मुख्यमंत्री गौतमबुद्धनगर में आयोजित उत्कर्ष नारी सम्मान, युवा स्वाभिमान कार्यक्रम के समापन समारोह में भी शामिल हुए।

सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए पहली अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमीट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग-यूपीपीएससी 2025 की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को समाज कल्याण विभाग की ओर से साक्षात्कार की विशेष तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए विभाग के द्वारा 23 सितंबर से विशेष मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम कई चरणों में संचालित होगा। मॉक इंटरव्यू का आयोजन गोमती नगर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन में किया जाएगा। इसके माध्यम से अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की बारीकियों, व्यक्तित्व प्रस्तुतीकरण और आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, सरकार 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से देश के कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन में आए बदलावों के बारे में।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानी पीएम-जनमन एक केंद्रित मिशन है, जिसका उद्देश्य भारत के कमजोर जनजातीय समूह को विकास से जोड़ना है। यह योजना विकास को आजीविका और आर्थिक अवसरों से भी जोड़ती है। इसके तहत 24000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी गई है। योजना के तहत जून 2026 तक, 2.67 लाख पक्के मकान पूरे हो चुके हैं, 8,473 गांवों में 100 प्रतिशत पाइप से पानी की आपूर्ति हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम जन मन योजना के जरिए होने वाला विकास आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर दे रहा है। बाइट....

पीएम जनमन योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे। कोई पूछने वाला नहीं था। गोरखपुर जनपद के ग्राम जंगल तिनकोनिया के राम गणेश ने बताया कि पीएम जनमन योजना से उनके गांव की तस्वीर बदल गई है। बाइट....

पीएम जन मन योजना के तहत लाभ मिला है जो कि हमारे गांव में कभी ना तो पानी मिलता था, ना बिजली मिलता था, ना तो राशन कार्ड मिलता था, ना तो हम लोग को मकान मिलता था। 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उसमें हम लोग को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास और बिजली आई। यह योजना कमजोर आदिवासी समुदायों को भारत के विकसित भारत की यात्रा के केंद्र में रखती है। गिरीश नारायण चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।

युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए सौ सप्ताह के नशा-मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देशभर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा-मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है।
